



निर्माण सिविल सर्विसेज मासिक पत्रिका

मार्च, 2019 (अंक: 8)

मुख्य संपादक :

कमलदेव सिंह

संपादक :

रजनीश कुमार

इम्तियाज खान

संपादकीय सलाहकार :

स्वदीप कुमार

सहयोगी :

मनीष प्रियदर्शी, तरुनेन्द्र कुँवर, सुब्रत पाण्डेय,  
शिल्पा देवी एवं सनी वर्मा

ग्राफिक्स एंड डिजाइन :

संतोष कुमार झा, पंकज तिवारी, सुनील कुमार  
एवं संतोष झा

© प्रकाशक

HEAD OFFICE

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi  
Vihar Bandh) Delhi-110009

ENQUIRY OFFICE

631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar,  
Delhi-09

Website: www.nirmanias.com

E-mail: nirmanias07@gmail.com

Ph.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797

## विषय सूची

इस अंक में...

### प्रश्नपत्र - (1)

सतत विकास और समय परिवर्तन	1
10 प्रतिशत आरक्षण	3
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018	4
वर्ष 2018 में जेमिनिड उल्का वर्षा	5
‘हंपी’	5
कुंभ	6
इंडिया स्टील 2019	7
पवित्र कैलास बनेगा राष्ट्रीय धरोहर	8
‘यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू योगा’	8
नेशनल वॉर मेमोरियल	9
शाहपुरकंडी बांध	10
तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2018	10
21 राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र इको सेंसिटिव घोषित	11
जल संरक्षण शुल्क	12
‘कड़कनाथ’	12
पंज तीरथ	13
बाल विज्ञान कांग्रेस	14
एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर लागू की सुरक्षा व्यवस्था	14
कुष्ठ तलाक का आधार नहीं	15
ओडीएफ भारत लक्ष्य प्राप्ति की ओर: रिपोर्ट	16
वेब-वंडर वुमन अभियान	17
‘खेलो इंडिया युवा खेलों’ का दूसरा संस्करण पुणे में शुरू	17
‘स्वदेश दर्शन’	17
चार और परियोजनाओं को मंजूरी	18
350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी	19
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019	19
उरुका उत्सव	20
मौसम की ज्यादा सटीक जानकारी	21
ASER रिपोर्ट 2018	21
विश्व संगीत महोत्सव	22
“सांझी-मुझ में कलाकार”	22
वर्ल्ड रैंकिंग: यूनिवर्सिटी	23
गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा	23
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	24
भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय	24
शहरी समृद्धि उत्सव	25
डीएमएफ/पीएमकेकेकेवाई पर प्रथम कार्यशाला	26

### प्रश्नपत्र - (2)

वेनेजुएला संकट	27
अमेरिकी शटडाउन	28
सैंस ‘पब्लिक अकाउंट’ में नहीं : कैंग	30
चाबहार का नियंत्रण भारत को	30
केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट	31
जस्टिस खन्ना और जस्टिस माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश	34

गिलगिट-बाल्टिस्तान को संवैधानिक दर्जा	34
15वाँ प्रवासी भारतीय दिवस	36
आधार कार्ड से नेपाल-भूटान की यात्रा को मंजूरी	37
भारत - मॉरीशस वार्ता	37
अमेरिका: सेना में ट्रांसजेंडर पर रोक	38
जनजातीय भारत आदि महोत्सव	38
संविधान की धारा -280 में संशोधन	39
आईसीएटी/केआईएपीआई के मध्य समझौता	39
‘अति उन्नत’ युद्धपोत	40
भारत, मोरक्को के मध्य द्विपक्षीय सहयोग	40
लोकसभा के 45 सदस्य निर्लंबित	41
लोकपाल	41
चीन ने बनाया महाबम	42
अपंगता को दूर करने की तकनीक	42
असम विधानसभा में आरक्षण	43
वेबकास्ट	43
डायबिटीज की जाँच	45
नॉर्वे के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा	46
ग्रीन कार्ड के सम्बन्ध में भारतीय दूसरे स्थान पर	47
नवोदय विद्यालयों में अतिरिक्त सीटों की मंजूरी	47
रेलवे के पुराने पुल दुर्घटना का कारण	48
ब्रेकिंग	48
रायसीना संवाद	49
समुद्री समझौता	49
भारत और फ्रांस के मध्य समझौता	50
H1B बीजा नियम	50
‘बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय विमर्श’	50
हुनर हाट	51
गुजरात में आरक्षण	52
वुमनिया ऑन (जीईएम)	52
विश्वविद्यालय में सीटें बढ़ेंगी	52
परिवार नियोजन नियम पर रोक	53
भारत और मालदीव के बीच समझौता	53
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता	53
स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी	54
स्कूलों में विज्ञान, गणित पढ़ाने में सहयोग करेंगे आईआईटी, आईआईएसईआर	54
चीन का महाशक्ति बनने का प्रयास	54
भारत जापान के बीच ऋण समझौता	55
भारत/उज्बेकिस्तान के मध्य यूरेनियम अनुबंध	55

### प्रश्नपत्र - ( 3 )

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड	56
बाबा कल्याणी समिति	57
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट	58
मुद्रा विनिमय प्रबंध प्रारूप	59
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण / GSAT-7A	60
‘गोल्डेन ब्लड’	61
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)	61
माइक्रोसॉफ्ट एआई-सेंसर	62

ई-नाम	63
सौर ऊर्जा/जल उपचार प्रौद्योगिकी मिशन केंद्र	64
कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस उत्पादन पर रिपोर्ट	64
माइक्रोसैट-आर और कलामसैट	65
पुनर्पूजीकरण से निवेश में मजबूती	66
निर्यातकों को 600 करोड़ की ब्याज सब्सिडी	67
यू. के. सिन्हा समिति	68
चांगी-4	68
भारतीय चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग	69
अनाज गुणवत्ता घोटाला	70
S-400	71
भोपाल मॉडल	74
भारतीय सेना में ‘एआई’ तकनीक	75
बहु-ब्रांड खुदरा में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं	76
आयात में संरक्षण हेतु प्रभावी कदम	79
समीक्षा : दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	79
नयी पेटेंट दवाओं को पांच साल की छूट	81
बिजली टैरिफ नीति	82
पाबुक तूफान	82
एचएएल बनाएगा हथियारबंद एलसीए तेजस	83
मोरेह में एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन	83
मेघालय सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना	83
FDP बिल	84
वैश्विक मंदी की आहट	84
डार्क वेब	85
जीएसटी में सुधार हेतु प्रस्ताव	86
केवाईसी का विस्तार	87
पेट्रोल पंपों पर मिलेगा फास्टैग	88
लेजर से सीमा सुरक्षा	89
2030 तक वैश्विक विमान यात्रा में 100 प्रतिशत वृद्धि	89
भारतीय नस्लों के पशुओं में सुधार हेतु तकनीक	90
DNA तकनीक बिल लोकसभा से पारित	91
बैंकिंग इकाइयों के रूप में सहकारिता मॉडल	91
सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत	92
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार	92
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना	92
सीवर लाइन की सफाई बैक्टीरिया से	93
छोटे उद्यमों को जीएसटी सीमा में छूट	93
प्रदूषण पर उच्च-स्तरीय समिति	94
औद्योगिक उत्पादन में गिरावट	95
भारत-चीन सीमा पर 44 सड़कों बनवाएगी सरकार-रिपोर्ट	95
ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया	96
नौवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	96
भारत में रोबोट संचालेगा ट्रैफिक	97
नया DNA टूल	97
‘डीडी साइंस’ और ‘इंडिया साइंस’ की शुरुआत	98
चांद पर पहला पौधा	99
रचनात्मक सामानों के निर्यात में भारत विश्व का अग्रणी देश	99
‘अपने बजट को जानिए’ पहल शुरू	100

भारत जलवायु परिवर्तन पर कार्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में एक अग्रणी देश	101
एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 परियोजना	101
भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूजीकरण को स्वीकृति 'सक्षम 2019'	102
पेट्रोल पंप से निकलने वाली खतरनाक गैस	103
सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	103
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	104
'उन्नति' इसरो का क्षमता निर्माण कार्यक्रम	104
टाइटन के उत्तरी हिस्से में मिथेन की बारिश	104
राष्ट्रीय कारोबार रजिस्टर	105
भारत की पहली लीथियम आयन गीगा फैक्ट्री	105
भारतीय नौसेना की क्षमता वृद्धि	106
मिलिट्री पुलिस में होगी 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती	106
भारत के साथ मिसाइल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा अमेरिका	106
रेलवे का संचालन निजी हाथों में	107
ट्रेन 18 का निर्यात	107
'स्टार्ट-अप इंडिया' योजना पर ग्रहण	108
इको निवास संहिता 2018	109
बिग बैंग के समय के अवशेष की खोज	110
कृषि निर्यात नीति 2018	111

#### प्रश्नपत्र - ( 4 )

भावनात्मक बुद्धि/निर्णयन में इसकी भूमिका	112
केस स्टडी	113

#### समसामयिक मुद्दों से संबंधित लेख

प्रारंभिक शिक्षा नीति में बदलाव	115
NRC तथा संकट	119

#### प्रारम्भिक परीक्षा विशेष : 2019

समसामयिक घटनाक्रम	123
एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019	123
अंतरिक्ष में जानवर नहीं रोबोट भेजेगा इसरो	123
भारत में सीदी समुदाय	124
विश्व आर्थिक मंच	124
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट	124
मणिपुर में पक्षी अभ्यारण्य	125
9 अमीरों के पास आधी आबादी जितनी संपत्ति	126
नेपाल में सिर्फ 100 रुपये का भारतीय नोट	126
भारत पर्व	126
बिहार की 2017-18 में सर्वाधिक जीडीपी ग्रोथ	127
2040 तक 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा	127
भारत और जापान सहयोग	127
भारत और कुवैत के मध्य समझौता	127
भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019	128
आईएन कुहासा	128
70वां गणतंत्र दिवस	129

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर	129
इंडोनेशिया में सुनामी	130
अंडमान द्वीपों के नाम परिवर्तन	130
वर्ष 2023 : अंतर्राष्ट्रीय बाजरा-ज्वार दिवस	130
आर्कटिक रेंडीयर की संख्या में गिरावट	131
भारत में प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन	131
टनेलबॉट	132
कोप-24 कैटोवाइस	133
वॉयजर-2	133
'2018 वी जी 18'	133
जीएसएलवी-एफ 11 से जीसैट-7ए का प्रक्षेपण	134
सुदर्शन पटनायक	134
इंडियन साइंस कांग्रेस	134
अरुणिमा सिन्हा	136
'स्वच्छ सर्वेक्षण 2019'	137
'भारतीय महिला जैविक उत्सव'	137
पहुंच	137
एडीएम क्रिस्टोफ प्राजुक का भारत दौरा	138
आईटी कानून की धारा 66ए	138
देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज	138
100वां विद्युत इंजन 'शतक'	139
शेख हसीना	139
76वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स	139
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार	140
विश्व बैंक अध्यक्ष का इस्तीफा	140
गीता गोपीनाथ	141
नंदन नीलेकणि समिति	141
तिब्बत सीमा पर चीन की तोपें	142
सड़क, सीवेज परियोजना	142
अप्सरा रेड्डी	142
कुमार राजेश चन्द्र	143
एलिजा किट्स	143
ब्रांड सेलेब्रिटी की सूची	143
निकोलस मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने	144
इंडिया एक्सपो मार्ट	144
कांगो में राष्ट्रपति चुनाव	144
प्रदूषण पर उच्च-स्तरीय समिति	144
संसद रत्न अवार्ड	145
विनेश फोगाट	145
राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार	145
शी बॉक्स	146
वन स्टॉप सेंटर	146
शाउट	147
25 राज्यों के सौ फीसदी घरों का विद्युतीकरण	147
जीसैट-11 का प्रक्षेपण	147
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018	147
नीति आयोग समीक्षा 2018	148
ज्ञान एवं नवाचार केंद्र	155
उद्यम संबंधी पारितंत्र को प्रोत्साहन	155

# प्रश्नपत्र-

# 1

## सतत विकास और समय परिवर्तन

### संदर्भ :

- सन् 1760 और 1840 के बीच पहली औद्योगिक क्रांति ने लौह और इस्पात के उपयोग और मानव श्रम को आसान बनाने का काम किया।
- 1870 और 1914 के बीच दूसरी औद्योगिक क्रांति पेट्रोलियम, कोयले और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत के रूप में जानी जाती है।
- इसके प्रभाव 1900 के दशक में प्रकट हुए थे। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पर पहला असंतोष दस्तावेज 1962 में राशेल कार्सन की 'साइलेंट स्प्रिंग' के रूप में सामने आई थी।
- यह बगों को मारने की नीयत से जीवमंडल में डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन (डीडीटी) के प्रवेश करने के बारे में था। इसने पक्षियों और मछलियों के माध्यम से खाद्य शृंखला पर हमला किया जो अंततः मानव तक पहुँच गया।
- साइलेंट स्प्रिंग एक शुरुआत थी। इसने दुनिया भर में पर्यावरणविद् के बारे में विचारों को जन्म दिया। 1970 में संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (यूएसईपीए) की स्थापना हुई।
- डीडीटी के कैंसरजनक होने की संभावना के आधार पर 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- यह पता चला कि यह गंजा ईगल के लिपिड में जमा होकर उसकी प्रजनन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है। राष्ट्रपति केनेडी ने राशेल कार्सन के दावे की जांच का जिम्मा विज्ञान सलाहकार समिति को दिया।
- बायोटा पर कीटनाशकों के प्रभावों का अध्ययन के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराया गया।
- पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो चिंताएं सामने आई उससे अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में नए कानून और नई पहलें आरंभ की गईं।
- वाइल्डरनेस प्रोटेक्शन एक्ट (1964), नेशनल वाइल्ड एंड सीनिक रिवर्स एक्ट (1965), संकटापन्न प्रजाति संरक्षण अधिनियम (1966) और पर्यावरण रक्षा निधि (1967) संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी पहलों के उदाहरण हैं।

## सततता की अवधारणा का विकास

- संयुक्त राष्ट्र ने 1968 में पेरिस में जैवमंडल के उचित उपयोग और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- जो कि वैश्विक जीवमंडल की सुरक्षा के लिए समर्पित है। पारिस्थितिक रूप से सतत विकास की अवधारणा पर प्रारंभिक चर्चाएं प्राकृतिक रूप से सतत विकास की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उनके संरक्षण पर केन्द्रित थी।
- पहला पृथ्वी दिवस 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया। 'प्रदूषक को भुगतान करना पड़ता है' सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश हिस्सों में पर्यावरण कानून का हिस्सा बन गया है। सतत् विकास की यात्रा के क्रम में यह एक मील का पत्थर था।
- 1971 तक फ्रांस, स्वीडन, कनाडा और जापान समेत कई देशों में, पर्यावरण की रक्षा के लिए मंत्रालयों या एजेंसियों का निर्माण किया गया।
- गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इन्होंने वाचडॉग के रूप में कार्य किया, सरकारी मशीनरी को कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित किया जहाँ मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा था वहाँ निगरानी की भूमिका अदा कर सरकार को कार्यवाही के लिए प्रेरित किया और इस तरह संरक्षण को बढ़ावा दिया।
- वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की उत्पत्ति हुई जिसका उद्देश्य सततता को बढ़ावा देना था।
- 1972 में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने 'विकास की सीमाएं' रिपोर्ट प्रकाशित की।
- इसमें पाया गया कि जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन, संसाधनों में कमी, औद्योगिक उत्पादन और प्रदूषण पृथ्वी पर विकास को सीमित करते हैं।
- साथ ही यह देखा गया कि पृथ्वी पर मौजूदा संसाधनों का संग्रह और विकास का जो स्तर है, उसको देखते हुए विकासात्मक गतिविधियों को वर्ष 2100 से परे जारी नहीं रखा जा सकता।

- ब्रुटलैंड की सतत विकास की क्लासिक परिभाषा 1987 में प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार मानवता में विकास को सतत करने की क्षमता निहित है। यह सुनिश्चित करते हुए कि अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरी करते हुए भावी पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं किए जाए।
- ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट, 'हमारा साझा भविष्य' के तीस वर्षों के बाद भी सतत विकास की यही परिभाषा पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है।

### ग्लोबल वार्मिंग की संकल्पना

- जब 19वीं सदी के अंत में मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा हुई, तब एक मत ने तर्क दिया कि ग्लोबल वार्मिंग भी प्राकृतिक शक्ति का ही परिणाम हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी की धुरी की अस्थिर गति से वैश्विक तापमान में परिवर्तन हो सकता है।
- मोलिना और रोवलैंड (1974) ने पहली बार बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उत्सर्जन और सीएफसी गैसों का अनियमित दर से निरंतर उपयोग ओजोन परत को गंभीर रूप से कम कर देगा।
- वर्ष 1985 में विश्व मौसम विज्ञान सोसाइटी, यूएनईपी और वैज्ञानिकों के संघ का अंतर्राष्ट्रीय परिषद की ऑस्ट्रेलिया में हुई बैठक में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के जमा होने की सूचना दी।

- फार्मन एवं अन्य (1985) ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में कमी आई है।
- 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, पृथ्वी के ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता अपनाया गया।
- ओजोन परत में क्षरण होने की दशा में हानिकारक पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल के निम्न परत में प्रवेश कर जाएगा। यह विकिरण त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ भूमि और पानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) से जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल (आईपीसीसी) का जन्म हुआ। उनके समेकित प्रयास ने वैश्विक समुदाय को यह स्पष्ट किया कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन मानव प्रेरित थे।
- वर्ष 2007 में आईपीसीसी को पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- अपने उद्घरण में, नोबेल समिति ने कहा कि 'आईपीसीसी और गोर को (मानव) जनित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक ज्ञान संचित करने और प्रसारित करने के उनके प्रयासों तथा ऐसे परिवर्तनों को टालने के लिए उपाय बताने के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया।'

### संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज

- 1990 में पहली आईपीसीसी आकलन रिपोर्ट ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती को कम करने में वैश्विक सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।
- इसके तुरंत पश्चात् ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु वैश्विक संधि के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) की स्थापना की गई।

### रियो शिखर सम्मेलन

- वर्ष 1991 के रियो शिखर सम्मेलन में, यूएनएफसीसीसी पर्यावरण और सतत विकास के मुख्य विषयों के साथ हस्ताक्षर के लिए खोला गया।
- वर्ष 1995 से, प्रत्येक वर्ष यूएनएफसीसीसी सदस्य देशों में से किसी एक देश में इस क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक करती है। अभी हाल में दिसंबर, 2018 में पोलैंड के कटोवाइस में इनका सम्मेलन हुआ।

### सतत विकास की वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2000 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को 2015 में प्राप्त करने का अनुमान लगाया था। इनमें आठ लक्ष्य थे जिनमें से सातवां लक्ष्य पर्यावरणीय सततता था।
- वर्ष 2015 में प्रकाशित समीक्षा रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अपनी कमियों के बावजूद एमडीजी विकसित और विकासशील देशों में निर्णय लेने में सफल रहा।
- वर्ष 2016 में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) निर्धारित किए गए जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरे किए जाने हैं।
- इसके 17 लक्ष्यों में से तेरहवां लक्ष्य जलवायु कार्यवाही से संबंधित है। एसडीजी पर 2017 की रिपोर्ट में बताया गया कि एसडीजी प्राप्त करने में प्रगति की गति अपर्याप्त हैं।
- सितंबर, 2018 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक भूख के मुख्य कारणों में से एक है।
- भूमि का क्षरण, मरुस्थलीकरण, पानी की कमी और बढ़ते समुद्री जल स्तर जैसी चरम घटनाओं के बढ़ने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि भूख के मुद्दे से निपटने के वैश्विक प्रयासों

को जलवायु परिवर्तन पराजित कर रहा है।

- दुनिया के कई हिस्सों में, जलवायु आपदाओं ने सतत विकास के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय योजनाओं को प्रभावित किया है। संभवतः इन योजनाओं में आपदाओं के प्रबंधन के लिए भी जगह बनाने का समय आ गया है।

### निष्कर्ष

- वर्ष 1962 में अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना से, सबसे हालिया संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2016 तक, मानव जाति के लिए पृथ्वी पर शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। लेकिन देर से यह महसूस किया गया है कि गरीबी, असुरक्षित आजीविका आदि जैसी मानव अनियमितताएं प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम रही है।
- इन प्राकृतिक घटनाओं से मानव जीवन को कितनी बाधाओं को सहन करना पड़ा है उसकी पहचान करने के लिए एक समेकित प्रयास की जरूरत है ताकि दुनिया भर के देश इन चिंताओं को दूर करने के लिए नीतिगत उपायों एवं उनके सफल क्रियान्वयन के द्वारा अपनी प्रतिबद्धता का वचन दे सकें।

## 10 प्रतिशत आरक्षण

### चर्चा में क्यों?

- सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केन्द्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी।

### मुख्य तथ्य :

- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए निर्धारित 50 फीसद के कोटे को छोड़े बिना सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का फैसला लिया है।
- इसका लाभ सवर्ण हिंदुओं के साथ-साथ सभी अनारक्षित जाति के गरीबों को मिलेगा।
- इसमें आर्थिक पिछड़ेपन की परिभाषा ओबीसी के समान ही रखी जाएगी।
- इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
- संविधान में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16 में किया गया है।

### इन्हें मिलेगा लाभ

- ऐसे परिवार, जिसकी सालाना आय आठ लाख या उससे कम होगी।
- जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।
- ऐसे परिवार जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का प्लॉट है।
- अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 109 गज का प्लॉट है।
- गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 209 या उससे कम का प्लॉट है।
- जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी तय कर रखा है।
- इन्दिरा साहनी मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों के फैसले के बाद आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी कर दिया गया था, जिस पर अब बदलाव होना मुश्किल है।
- सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एमएच कानिया की अध्यक्षता में नौ जजों की बेंच ने 1992 में आरक्षण के सभी पहलुओं पर विस्तार से फैसला दिया था।
- सामाजिक और राजनीतिक न्याय के मद्देनजर कमजोर वर्गों को आरक्षण देने को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। सरकारी नौकरियों में मेरिट नजरअंदाज नहीं हो, इसलिए 50 फीसदी की सीमा भी तय कर दी गई थी।
- राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में जाट और मराठों को आरक्षण का मामला न्यायिक हस्तक्षेप की वजह से अमल में नहीं आ सका।
- गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए भारत सरकार का फैसला भी आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में अटक सकता है।

### संविधान में बदलाव

- यह आरक्षण आर्थिक आधार पर लाया गया जिसकी अभी तक संविधान में व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा।
- इसके लिए अनुच्छेद 15 और 16 में एक-एक उपबंध जोड़ा गया और सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।

### आधार

- सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला सिन्हा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया है।



- सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसआर सिन्हा की अध्यक्षता में 2006 में एक आयोग का गठन किया गया था। इसने 22 जुलाई, 2010 को अपनी रिपोर्ट दी थी।
- रिपोर्ट में सामान्य जातियों के गरीब लोगों को भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी।

अभी किसको कितना आरक्षण	
● अनुसूचित जाति (एससी)	15 फीसद
● अनुसूचित जनजाति (एसटी)	7.5 फीसद
● अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	27 फीसद
● कुल आरक्षण	49.5 फीसद

**प्र. आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण किस हद तक भारतीय समाज को समावेशी बनाने में सहायक है? भारतीय समाज के और अधिक समावेशी विकास के लिए क्या किये जाने की आवश्यकता है?**

### वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018

#### संदर्भ :

- वर्ष 2018 के लैंगिक अंतराल सूचकांक (Global Gender Gap Index 2018) में विश्व के 149 देशों के सूचकांकों में भारत को 108वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है।
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाने वाले इस सूचकांक में वर्ष 2017 में भी भारत इसी रैंक पर था, अर्थात् ओवरऑल उसकी रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

#### मुख्य तथ्य :

- रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 66.5 प्रतिशत जेंडर गैप को कम करने में सफल रहा है परंतु अभी भी 33.5 प्रतिशत लैंगिक असमानता की खाई को कम करना शेष है।
- जेंडर गैप मापन के चारों मानकों में विगत वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।
- स्वास्थ्य व उत्तरजीविता के मामले में तो भारत विश्व में तीसरा सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाला देश है।
- हालांकि रिपोर्ट के अनुसार समान कार्य के लिए मजदूरी के स्तर पर भारत में सुधार देखा गया है और टर्शियरी स्तर की शिक्षा (कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल) में पहली बार भारत लैंगिक असमानता की खाई को पूरी तरह समाप्त करने के करीब पहुँच गया है।
- रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में एक और विरोधाभास की ओर इशारा किया गया है।

- भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस श्रम बल वाला देश है, साथ ही विश्व में सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस लैंगिक अंतराल वाला देश भी है।

- भारत में पुरुषों के 78 प्रतिशत के मुकाबले केवल 22 प्रतिशत महिलाएं श्रम बल ही इस क्षेत्र में हैं।

#### अन्य बिन्दु :

- वैश्विक स्तर पर, रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में जेंडर गैप में सुधार के बावजूद स्वास्थ्य व शिक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में ट्रेंड प्रतिकूल होता हुआ दिखाई दिया।
- परिवर्तन की वर्तमान दर जारी रहने पर 108 वर्षों के बाद ही जाकर पुरुष एवं महिला में असमानता की खाई को लगभग पाटा जा सकता है।
- हालांकि आर्थिक स्तर पर समानता प्राप्त होने में 202 वर्ष लग जाएंगे। विश्व आर्थिक मंच की इस सूचकांक में सर्वोच्च रैंकिंग आइसलैंड को प्राप्त हुई है।
- मतलब यह कि विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश आइसलैंड है।
- हालांकि वह भी पूर्ण लैंगिक समानता वाला देश नहीं है। वहाँ 85 प्रतिशत लैंगिक असमानता को समाप्त कर लिया गया है। आइसलैंड के पश्चात स्वीडन और फिनलैंड का स्थान है।

विभिन्न मानकों पर विश्व में भारत की लैंगिक अंतराल रैंकिंग		
	2018	2019
● ओवरऑल रैंकिंग	108	108
● आर्थिक भागीदारी व अवसर	142	139
● शैक्षिक उपलब्धि	114	112
● स्वास्थ्य व उत्तरजीविता	147	141
● राजनीतिक सशक्तिकरण	19	15

ग्लोबल जेंडर गैप वैश्विक रैंकिंग		
देश	रैंकिंग 2018 ( स्कोर )	रैंकिंग 2017 ( स्कोर )
आइसलैंड	1 (0.858)	1 (0.878)
नॉर्वे	2 (0.835)	2 (0.830)
स्वीडन	3 (0.822)	3 (0.816)
फिलीपींस	8 (0.799)	8 (0.790)
बांग्लादेश	48 (0.721)	48 (0.719)
यूएसए	1(0.720)	1(0.718)
चीन	51 (0.720)	51 (0.674)
भारत	103 (0.673)	103 (0.669)
पाकिस्तान	148 (0.550)	148 (0.546)
यमन	149 (0.499)	149 (0.516)